

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक :प.जि.न्याया./स्था./दर संविदा/फोटो कॉपी/2023-24/60

दिनांक : 25/01/2024

बोली सूचना संख्या 01/2023-24


(NIB No. CJK2324A0001.....) (UBN No. CJK2324SS0B000001)

कोटा न्यायक्षेत्र में कोटा मुख्यालय स्थित नकल शाखा में प्रतिलिपियों हेतु फोटो स्टेट कार्य दर संविदा **वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 31.03.2025)** के लिये राज लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-29 के अनुसरण में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र० सं०	विवरण	कार्यावधि	अनुमानित राशि रु.	बोली प्रतिभूति राशि (EMD)रु.	बोली शुल्क रु.	बोली विक्रय तिथि	बोली प्राप्ति तिथि	बोली खोलने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	केन्द्रीयकृत नकल शाखा में फोटोस्टेट कार्य	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	9,00,000/- (वार्षिक)	18,000/-	1000/-	बोली प्रकाशन तिथि से 17.02.2024 तक	19.02.2024 को दोपहर 02.00 बजे तक	19.02.2024 को सांय 04.00 बजे

प्रतिलिपि हेतु शर्तें-

- बोलीदाता को नकल शाखा का फोटो स्टेट कार्य सुगम संचालन हेतु **तीन हाईस्पीड फोटो स्टेट मशीनें (न्यूनतम 24 सीपीएम) मय ऑपरेटर स्थापित करना अनिवार्य होगा।**
- सफल बोलीदाता को कार्य आरम्भ करने के पूर्व अधिकतम 7 दिवस में न्यायालय परिसर में स्थापित बैंक अथवा न्यायालय परिसर से 200 मीटर की परिधि में स्थित बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा।
- बोली प्रपत्र किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में बोली प्रकाशन तिथि से अथवा दिनांक 29.01.2024 से 17.02.2024 को कार्यालय समय तक में बोली शुल्क 1000/-रूपये नगद में जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।
- फोटो कॉपी/ जेरोक्स का कार्य करने वाली फर्मों को बोली का विक्रय किया जा सकेगा।**
- भरी हुई बोलीयां दिनांक **19.02.2024 को 02:00 बजे तक** स्वीकार की जावेगी, तत्पश्चात प्राप्त बोलीयों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- प्राप्त बोलियां दिनांक **19.02.2024 सायं 04:00 बजे** उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण राजस्थान लोक उपापन पोर्टल sppp.raj.nic.in एवं जिला न्यायालय की वेब साईट <https://districts.ecourts.gov.in/kota> पर भी उपलब्ध है।



 अध्यक्ष,
 (फोटो कॉपीयर नियुक्ति समिति)
 जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक :प.जि.न्याया./स्था./दर संविदा/फोटो कॉपी/2023-24/1391-1411

दिनांक : 25/01/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी/बांसी/झालावाड/उदयपुर/जोधपुर महानगर/जयपुर महानगर/भरतपुर/बीकानेर/अजमेर
- संभागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलेक्टर, कोटा/कोषाधिकारी, कोटा को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने हेतु।
- सूचना जन सम्पर्क विभाग, जयपुर वास्ते सूचना प्रकाशित करवाने बाबत।
- प्रभारी अधिकारी नकल शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा उचित प्रचार प्रसार हेतु।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, कोटा को बोली विज्ञप्ति एवं बोली प्रपत्र को राज0 लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय वेब साईट पर अविलम्ब अपलोड करने बाबत।
- केशियर, जिला न्यायालय, कोटा को बोली प्रपत्र विक्रय करने एवं विक्रय का विवरण प्ररूप (S.R-9) में संधारित करने हेतु।
- कार्यकारी लिपिक, केन्द्रीयकृत प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा को निर्धारित प्ररूप(S.R- 10) में बोली प्राप्ति पंजिका संधारित करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, कोटा
- स्थानीय फर्म.....


 अध्यक्ष,
 (फोटो कॉपीयर नियुक्ति समिति)
 जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक :प.जि.न्याया./स्था./दर संविदा/फोटो कॉपी/2023-24/60

दिनांक : 25/01/2024

बोली सूचना संख्या 01/2023-24


(NIB No.) (UBN No.)

कोटा न्यायक्षेत्र में कोटा मुख्यालय स्थित नकल शाखा में प्रतिलिपियों हेतु फोटो स्टेट कार्य दर संविदा **वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 31.03.2025)** के लिये राज लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-29 के अनुसरण में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र० सं०	विवरण	कार्यावधि	अनुमानित राशि रू.	बोली प्रतिभूति राशि (EMD)रू.	बोली शुल्क रू.	बोली विक्रय तिथि	बोली प्राप्ति तिथि	बोली खोलने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	केन्द्रीयकृत नकल शाखा में फोटोस्टेट कार्य	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	9,00,000/- (वार्षिक)	18,000/-	1000/-	बोली प्रकाशन तिथि से 17.02.2024 तक	19.02.2024 को दोपहर 02.00 बजे तक	19.02.2024 को सांय 04.00 बजे

प्रतिलिपि हेतु शर्तें-

- बोलीदाता को नकल शाखा का फोटो स्टेट कार्य सुगम संचालन हेतु **तीन हाईस्पीड फोटो स्टेट मशीनें (न्यूनतम 24 सीपीएम) मय ऑपरेटर स्थापित करना अनिवार्य होगा।**
- सफल बोलीदाता को कार्य आरम्भ करने के पूर्व अधिकतम 7 दिवस में न्यायालय परिसर में स्थापित बैंक अथवा न्यायालय परिसर से 200 मीटर की परिधि में स्थित बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा।
- बोली प्रपत्र किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में बोली प्रकाशन तिथि से अथवा दिनांक 29.01.2024 से 17.02.2024 को कार्यालय समय तक में बोली शुल्क 1000/-रूपये नगद में जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।
- फोटो कॉपी/ जेरोक्स का कार्य करने वाली फर्में को बोली का विक्रय किया जा सकेगा।**
- भरी हुई बोलीयां दिनांक **19.02.2024 को 02:00 बजे तक** स्वीकार की जावेगी, तत्पश्चात प्राप्त बोलीयों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- प्राप्त बोलियां दिनांक **19.02.2024 सांय 04:00 बजे** उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण राजस्थान लोक उपापन पोर्टल sppp.raj.nic.in एवं जिला न्यायालय की वेब साईट <https://districts.ecourts.gov.in/kota> पर भी उपलब्ध है।



 अध्यक्ष,
 (फोटो कॉपीयर नियुक्ति समिति)
 जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक :प.जि.न्याया./स्था./दर संविदा/फोटो कॉपी/2023-24/1391-1411

दिनांक : 25/01/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी/बारां/झालावाड/उदयपुर/जोधपुर महानगर/जयपुर महानगर/भरतपुर/बीकानेर/अजमेर
- संभागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलेक्टर, कोटा/कोषाधिकारी, कोटा को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने हेतु।
- सूचना जन सम्पर्क विभाग, जयपुर वास्ते सूचना प्रकाशित करवाने बाबत।
- प्रभारी अधिकारी नकल शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा उचित प्रचार प्रसार हेतु।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, कोटा को बोली विज्ञप्ति एवं बोली प्रपत्र को राज0 लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय वेब साईट पर अविलम्ब अपलोड करने बाबत।
- केशियर, जिला न्यायालय, कोटा को बोली प्रपत्र विक्रय करने एवं विक्रय का विवरण प्ररूप (S.R-9) में संधारित करने हेतु।
- कार्यकारी लिपिक, केन्द्रीयकृत प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा को निर्धारित प्ररूप(S.R- 10) में बोली प्राप्ति पंजिका संधारित करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, कोटा
- स्थानीय फर्में.....


 अध्यक्ष
 (फोटो कॉपीयर नियुक्ति समिति)
 जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,कोटा

[RTPP नियम-36(2)]

कीमत 1000/-

बोली प्रपत्र

बोली सूचना संख्या- 01/2023-24

बोली प्राप्ति दिनांक 19.02.2024 को 2.00 बजे तक

बोली खोलने की दिनांक 19.02.2024 सायं 4.00 बजे

राज लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-29 (2)



1. कार्य का नाम : **क्रेन्दीयकृत प्रतिलिपि शाखा में प्रतिलिपियों हेतु फोटो स्टेट कार्य की दर संविदा**
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :
3. बोली शुल्क की राशि 1000/- नकद रसीद संख्या.....
दिनांक..... द्वारा जमा करा दी गई है।
4. बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) 18000/- जमा का बैंक ड्राफ्ट संख्या.....
दिनांक..... बैंक का नाम..... संलग्न कर दिया है।
5. बोली में अंकित कार्य का अनुमानित मूल्य 9,00,000/-रूपये है।
6. फर्म द्वारा **वित्तीय वर्ष 2024-25 (दि.01.04.2024 से 31.03.2025)** के लिए कार्य किया जावेगा। जो कार्यादेश जारी करने के पश्चात् 01.04.2024 से प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
7. उक्त कार्य दिनांक 31.03.2025 तक के लिए विधि मान्य हैं।
8. किये जाने वाले कार्य का विवरण निम्नानुसार है, कार्य हेतु फर्म की दरें संलग्न बोली प्रपत्र में अंकित की जावे।

क्र० सं०	नाम सामग्री	विशिष्टियां	अनुमानित संख्या	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5
1	लीगल साईज पेपर पर फोटो स्टेट कार्य	फोटो स्टेट कार्य (पेपर के एक तरफ) (जीएसएम 70)	750000/- (वार्षिक)	900000/- (वार्षिक)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय
नाम व पता :

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने जिस कार्य की विशिष्टियां दी हैं उस कार्य का मैं/हम अनुभव रखते हैं और भली भांति सम्पन्न कर सकते हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जावे तथा बोली रद्द कर दी जावे। मैंने/हमने बोली की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय फर्म मोहर
नाम व पता

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा



बोली दस्तावेज मूल्य=1000/-

बोली प्राप्ति दिनांक 19.02.2024 समय 2.00 बजे
बोली खोलने का दिनांक 19.02.2024 समय 4.00 बजे

बोली आमंत्रण सूचना संख्या- 01/2023-24

बोली निविदा प्रपत्र विशिष्टियां

क्रम संख्या	नाम कार्य	विशिष्टियां	अनुमानित मात्रा वार्षिक	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली दर प्रति पृष्ठ (सभी कर सहित)
1	2	3	4	5	6
1	केन्द्रीयकृत प्रतिलिपि शाखा में फोटोस्टेट कार्य	70 GSM लीगल पेपर	750000	900000/-	

नोट-

- ओवरसाइटिंग नहीं करें तथा कटिंग/कॉट-छांट पर हस्ताक्षर करें।
- दर अंकों एवं शब्दों में प्रति पृष्ठ अंकित करें।
- केवल एक ही दर अंकित की जानी है, एक से अधिक दर अंकित होने की स्थिति में केवल न्यूनतम दर ही स्वीकार्य होगी।
- दर प्रस्ताव बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के अध्यक्षीन प्रस्तुत किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मोहर



कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

बोली के लिए आवश्यक शर्तें :- [आर.टी.पी.पी. नियम -36(3)]

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक 15 बी/2/74/1004 दिनांक 14.03.84 के अनुसरण में एवं साधारण नियम (सिविल एवं फौजदारी) 2018 के आदेश 6 नियम 5 की अनुपालना में कोटा मुख्यालय पर फोटोस्टेट प्रतिलिपियां तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 31.03.2025) के लिये फोटो कोपियर्स की नियुक्ति की जाती है। जिस हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं:-

1. बोलीयां विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी जिन्हे इस कार्यालय से 1000/- रुपये नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी। आर.टी.पी.पी. नियम 45 (1) के अनुसार बोली दस्तावेज एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का संदाय भरे हुऐ बोली दस्तावेज के साथ डी0डी0 द्वारा किया जा सकेगा।
2. फोटो कॉपी/ जेरोक्स करने वाली फर्मों को बोली का विक्रय किया जा सकेगा।
3. बोलीयां बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तों के प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित की जाकर प्रस्तुत करनी होगी, लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "केन्द्रीयकृत प्रतिलिपि शाखा में प्रतिलिपियों हेतु फोटो स्टेट कार्य दर संविदा एवं बोली सूचना संख्या" लिखा होना चाहिये।
4. बोली प्रपत्र बोली प्रकाशन की तिथि से दिनांक 17.02.2024 तक कार्यालय समय में विक्रय की जावेगी, विक्रित बोलीयां दिनांक 19.02.2024 को दोपहर 02:00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत की जा सकेंगी। निर्धारित अवधि में प्राप्त बोलीयां दिनांक 19.02.2024 को सायं 04:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष, अध्यक्ष (ADJ-5) उपापन समिति के अवकाशागार में खोली जावेगी। यदि इस दिनांक को न्यायालय में अवकाश घोषित हो जाता है, तो समस्त कार्यवाही अंकित समयनुसार अगले कार्य दिवस में की जावेगी।
5. जो फोटो कॉपी तैयार की जावेगी वह साफ-सुथरी होगी। जिन प्रलेख पत्रों की फोटो प्रतियां तैयार की जावेगी, उनके संबंध में किसी को सूचना नहीं देंगे अर्थात पूर्णतया गोपनीयता बरती जावेगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा हाईस्पीड हेवी ड्यूटी (न्यूनतम 24 सीपीएम) की तीन फोटो स्टेट मशीन मय तीन फुल टाईम ऑपरेटर्स के साथ केन्द्रीयकृत प्रतिलिपि शाखा में स्वयं के खर्च पर लगानी होगी। इसके अलावा एक मशीन रिजर्व में रखनी होगी। बिजली, कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी परन्तु बिजली की राशि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा पृथक से सबमीटर की रीडिंग के अनुसार समय समय पर निर्धारित/परिवर्तित दर से अदा करना होगा।
7. फोटो स्टेट मशीनें नई/अच्छी कण्डीशन की होकर सुचारू रूप से कार्य करे, यह सुनिश्चित करना होगा। फोटो कॉपी मशीनों में तकनिकी खराबी होने पर संबंधित फर्म को अविलम्ब दूसरी फोटो स्टेट मशीन की व्यवस्था करनी होगी। फोटोकॉपी मशीनों की मरम्मत, अनुरक्षण, कागज सम्बन्धित समस्त प्रकार का व्यय स्वयं बोलीदाता को वहन करना होगा।
8. सफल बोलीदाता को तीन हाईस्पीड हेवी ड्यूटी (न्यूनतम 24 सीपीएम) फोटो स्टेट मशीनें मय फुल टाईम निपुण ऑपरेटर सहित स्थापित करनी होगी। फर्म/बोलीदाता को प्रत्येक दिन की प्रतिलिपियां उसी दिन मुख्य प्रतिलिपिकार के निर्देशानुसार व्यवस्थित रूप से तैयार करनी होगी। विशेष कार्यभार उत्पन्न होने की स्थिति में उसी दिन कार्य निष्पादित करने के दृष्टिकोण से बोलीदाता को अतिरिक्त फोटोकॉपी मशीन मय ऑपरेटर लगानी होगी एवं कार्यालय समय के पश्चात भी कार्य निष्पादित/ सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
9. बोलीदाता किसी अन्य अभिकरण को ठेका या उसका कोई भाग उप पट्टे पर नहीं दे सकेगा।



10. बोली में वर्णित अनुसार फोटोकॉपी हेतु 70 GSM अच्छे/ब्राण्डेड फोटोस्टेट पेपर ही उपयोग में लिया जायेगा तथा फोटोकॉपी सिंगल साइड की जावेगी एवं इस हेतु 70 GSM अच्छे/ब्राण्डेड फोटोस्टेट पेपर का नमूना मय ब्राण्ड लिखकर संलग्न करना होगा। आधी अधूरी प्रिंट, अस्पष्ट कॉपी, गलत फोटोकॉपी कर देने आदि से होने वाले पेपर वेस्टेज की जिम्मेदारी सम्बन्धित बोलीदाता फर्म की होगी।
11. बोलीदाता की दरें सभी कर एवं लागत यथा श्रम, स्याही आदि सहित होगी तथा सफल बोलीदाता को इस फोटो स्टेट कार्य पर लगने वाले आयकर अथवा अन्य सभी प्रकार के कर का भुगतान का दायित्व बोलीदाता फर्म का स्वयं का रहेगा।
12. बोली स्याही अथवा टंकण से भरी जावे। पेन्सिल से भरी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. न्यूनतम दरें वाली बोली को स्वीकार करने के लिये समिति बाध्य नहीं होगी अर्थात वह बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है, जिसका कि पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. समिति को फोटोकॉपी का कार्य गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर बोली का निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति न्यूनतम बोलीदाता व बोलीदाताओं को नेगोसिएशन के लिए आमंत्रित कर सकती है, इसके बावजूद दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवत्ता की न होने पर अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से भी बोली निरस्त की जा सकती है, जिसके लिए बोलीदाता को कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
15. यदि फोटोकॉपी का कार्य जिला एवं सेशन न्यायालय प्रशासन की संतुष्टि के आधार पर नहीं किया जाता है तो फर्म की संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है व अन्य फर्म से कार्य करवाने पर अन्तर की राशि के भुगतान के लिए बोलीदाता फर्म जिम्मेदार रहेगी।
16. सफल बोलीदाता बोली खुलने के पश्चात किन्तु बोली स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है या रूपान्तरित करता है या विहित करार निष्पादित नहीं करता या बोली स्वीकार करने के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (SD) जमा नहीं कराता या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है तो बोली प्रतिभूति (EMD) राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. कार्यादेश जारी करने के उपरान्त दिनांक 01.04.2024 से कार्य आरम्भ करना आवश्यक होगा। कार्य प्रारंभ करने में असफल होने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) जप्त कर कार्यादेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
18. प्रतिदिन होने वाली सकल प्रतिलिपियों की संख्या का बोलीदाता की स्वीकृत बोली दर से गुणा किया जाकर बोलीदाता को दैनिक आधार फर्म का बिल/वाउचर प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा। भुगतान फर्म/व्यक्ति को बैंक खाते के माध्यम से ही किया जावेगा। बैंक खाता कोर्ट परिसर में स्थित बैंक अथवा लगभग 200 मीटर की परिधि में स्थित बैंक में होना अनिवार्य है।
19. सफल बोलीदाता बोली स्वीकृति की अधिनिर्णय तिथि से सात दिवस में आरटीपीपी नियम 70(7)सपठित 76(2) के अनुसार अपेक्षित मूल्य के न्यायिकेत्तर स्टाम्प पर एस0आर0 प्रारूप 17 में एक करार निष्पादित कर कुल अनुमानित मूल्य (कार्यादेश राशि) की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (एस0डी0) राशि जर्ने ड्रॉपट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पक्ष में जमा करवाना होगा तथा न्यायालय परिसर अथवा 200 मीटर की परिधि में बैंक खाता संचालित होने की पूर्ण विगत मय खाता संख्या उपलब्ध करवायेगा।
20. दरें नियत स्थान पर अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। कांट-छांट व ओवर राइटिंग पर आवश्यक रूप से हस्ताक्षर किये जावें।



21. संविदा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा का निर्णय अंतिम होगा जो बोलीदाता को आवश्यक रूप से मान्य होगा।
22. बोली के साथ नियमानुसार 18,000/- रुपये का बोली प्रतिभूति (ई0एम0डी0) राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पक्ष में जमा कराना होगा।
23. सफल बोली दाता को कुल अनुमानित बोली लागत राशि का नियमानुसार 5 प्रतिशत कार्य सम्पादित (एस0डी0) प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पक्ष में दर स्वीकृति का अधिनिर्णय जारी होने से अन्दर सात दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. बोली में अंकित विशिष्टियों में किसी प्रकार परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
25. कार्य पर किसी भी प्रकार का कर/शुल्क देय होने की स्थिति में उसका भार बोलीदाता पर होगा। दरें समस्त शुल्क/कर सहित प्रस्तुत की जावेगी।
26. कार्य की मात्रा (लगभग 7,50,000 प्रतिघों वार्षिक) अनुमानित है जिसमें कमी/बेशी हो सकती है। फोटोकॉपी का कार्य बोली सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम या अधिक करवाया जाता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
27. दरें दिनांक 31.03.2025 तक मान्य होंगी। उक्त दरों पर कार्य आपसी सहमति से आरटीपीपी नियम लोक उपापन 29 (2)(झ)सपठित 73(3) के अनुसार अभिवृद्धित किया जा सकेगा।
28. बोली शर्तों के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा मंशा के संबंध में बोली खरीदने/डालने से पूर्व कार्यालय में उपापन समिति से स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।
29. यदि विभागीय जेरोक्स मशीन उपलब्ध हो जाती है तो एक माह का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा।
30. आरटीटीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम के समस्त प्रावधान उक्त दर संविदा कार्य पर प्रमावी एवं लागू होंगे।
31. आरटीटीपी नियम-2013 के नियम 48 (1) के अनुसार बोली की विधि मान्यता अवधि बोली खुलने की तारीख से 90 दिन तक मान्य होगी। किन्तु अपवादिक परिस्थिति में पारस्परिक सहमति से विधि मान्यता अवधि अभिवृद्धित की जा सकेगी।
32. किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायक्षेत्र कोटा शहर रहेगा।
33. पात्रता के मानदण्ड—
 - a. बोलीदाता अपने सेट-अप में किये गये कार्य के नमूने को संलग्न करेगा। समिति या उसके प्रतिनिधि बोलीदाता की कार्य क्षमता का निरीक्षण कर तदानुसार निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 - b. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करवाना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
 - c. दिवालिया/रिसीवर के अधीन/शोधन अक्षम नहीं/या अन्य प्रकार से बिजनेस करने से अयोग्य बोली हेतु सक्षम नहीं होंगे।
34. अमानत राशि/बोली प्रतिभूति राशि— असफल बोलीदाताओं को उनके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति (EMD) अमानत राशि बोली के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इस राशि पर किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।
35. प्रतिभूति राशि का समपहरण— निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगा—
 - a. जब संविदा में किन्हीं निर्बन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।



- b. जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो।
- c. जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए बोलीदाता को नोटिस दिया जाएगा।
- d. कार्य संपादन प्रतिभूति (SD) निक्षेप राशि का प्रतिदाय अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात् किया जाएगा।

36. बोलीदाताओं की अपात्रता-

- a. बोली सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुई बोलीयां।
- b. बिना बोली मूल्य एवं बोली प्रतिभूति राशि के जमा बोलीयां
- c. अपूर्ण बोलीयां
- d. भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली बोलीयां
- e. विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी से प्रदान करना।
- f. एक से अधिक बोली प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त बोलीयां मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
- g. अपूर्ण एवं सशर्त बोली प्रस्तुत करना।
- h. बोलीदाताओं अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
- i. अल्प वैद्यता वाली बोली प्रस्तुत करना।

अन्य नियम एवं शर्तें-

- a. बोलीदाता स्वयं के अधीनस्थ कर्मियों के चाल-चलन एवं चरित्र के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
- b. बोलीदाता स्वयं के अधीनस्थ कर्मियों के वेतन, भत्तों के भुगतान अथवा किसी प्रकार के बीमों की आवश्यकता हो तो उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके अधीनस्थ कर्मी स्वयं उसी के अधीनस्थ होंगे, जो किसी भी प्रकार से न्यायालय के कर्मी नहीं होंगे, ना ही इस प्रकार का दावा प्रस्तुत करेंगे।
- c. सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा फोटोस्टेट मशीन ऑपरेट करने के लिए लगाये जाने वाले कर्मचारी का किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, ना ही उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित हो तथा इस आशय का शपथपत्र मशीन ऑपरेटर कर्मचारी को लगाने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ व समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

दिनांक

शर्तों की स्वीकृति के समर्थन में
बोलीकार/फर्म के हस्ताक्षर, मय मोहर



Annexure -A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
 - (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
 - (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



Annexure B
Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement ofin response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/we.....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place : Kota

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :



Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be.
- (4) Appeals not to lie in certain cases:-
No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-
(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality
- (5) Form of Appeals:-
(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6) Fee for filing Appeal:-
(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of Appeal:-
(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
(b) On the date fixed for hearing, the appellate authority, as the case may be shall.
(i) Hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.



Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely:-

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.